*बैंकिंग सेवाओं की आपूर्ति और ऋण उठाव: पूर्वी क्षेत्र में आकांक्षी जिला कार्यक्रम से साक्ष्य**

राखी पी. बालचंद्रन ^ और बरखा गुप्ता ^ द्वारा

आर्थिक पिछड़ेपन के करीब होने के बावजूद, पूर्वी क्षेत्र के आकांक्षी जिलों में ऋण मध्यस्थता के विभिन्न स्तर दिखते हैं। हम इसकी जांच करते हैं कि क्या यह प्रवृत्ति बैंकिंग सेवाओं की आपूर्ति या बैंकिंग सेवाओं की मांग से प्रेरित है। सिस्टम जीएमएम ढांचे का उपयोग कर, हम पाते हैं कि संभावी शाखा विस्तार, ऋण मध्यस्थता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार, आर्थिक गतिविधियों के निम्न स्तर के कारण पिछड़े क्षेत्रों में कथित कम शाखा व्यवहार्यता के कारण बैंकों के शाखा विस्तार में धीमापन नहीं आता। साक्ष्य बताते हैं कि शाखा विस्तार, औपचारिक बैंकिंग चैनलों में अब तक अप्रयुक्त ऋण मांग का उपयोग करता है।

प्रस्तावना

आर्थिक संवृद्धि में ऋण मध्यस्थता की भूमिका साहित्य में एक सुस्थापित आर्थिक संबंध है। इसलिए, पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में वित्तीय मध्यस्थों के नेटवर्क का विस्तार महत्वपूर्ण हो जाता है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी शाखा प्राधिकरण नीति को उदार बनाकर बैंकों के शाखा नेटवर्क को अब तक बैंक रहित/कम बैंक वाले ग्रामीण केंद्रों (यूआरसी) की ओर प्रेरित कर रहा है। मौजूदा नीति के अनुसार, एक वर्ष में 25 प्रतिशत नए बैंकिंग आउटलेट यूआरसी में खोले जाने हैं। इसके अलावा, बैंकों को ग्रामीण बैंकिंग आउटलेट को बंद/स्थानांतरित/विलय करने से पहले आवश्यक अनुमोदन लेना होगा। दूसरी ओर, भारत सरकार द्वारा 2018 में शुरू किया गया आकांक्षी जिला कार्यक्रम, (एडीपी) भारत के पिछड़े जिलों के आर्थिक विकास के लिए, एक अभिनव दृष्टिकोण है। इन जिलों का चयन स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में आर्थिक अभाव और पिछड़ेपन के ग्यारह संकेतकों के आधार पर किया गया है। हालाँकि, सी-डी अनुपात के माध्यम से मापी गई बैंकों द्वारा ऋण मध्यस्थता, पिछड़ेपन के करीब होने के बावजूद इन जिलों में विषम है, इस प्रकार ऋण मध्यस्थता और आर्थिक संवृद्धि के बीच संबंध अस्पष्ट है। हालांकि, साहित्य में इस बात के प्रमाण हैं कि ऋण मध्यस्थता आर्थिक संवृद्धि की ओर ले जाती है, आर्थिक संवृद्धि से लेकर ऋण मध्यस्थता तक के विपरीत कारण साहित्य में भी स्वीकार किए जाते हैं। यह हमें आकांक्षी जिलों की ऋण मध्यस्थता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की पड़ताल करने के लिए प्रेरित करता है।

पूर्वी क्षेत्र के आकांक्षी जिलों में सी-डी अनुपात को नियंत्रित करने वाले कारकों की, प्रणाली जीएमएम प्राक्कलन का उपयोग कर, एक गतिज पैनल ढांचे में जांच की जाती है। चरों की गतिशील प्रकृति का ध्यान रखने के अलावा प्रणाली जीएमएम ढांचे में ऋण मध्यस्थता और आर्थिक संवृद्धि के बीच अंतर्जातता, को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाता है। ऋण मध्यस्थता और आर्थिक संवृद्धि के बीच अंतर्जातता बैंकों द्वारा उन क्षेत्रों में अधिक शाखाएं खोलने की प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न होती है जो आर्थिक गतिविधियों से भरपूर हैं, अर्थात् ऋण-मांग, बैंकिंग सेवाओं की उच्च आपूर्ति चाहती है। दूसरी ओर, बैंकिंग सेवाओं की उच्च आपूर्ति आर्थिक गतिविधियों के वित्तपोषण के माध्यम से ऋण मध्यस्थता को बढ़ाएगी, यानी बैंकिंग सेवाओं की आपूर्ति ऋण-मांग उत्पन्न करती है। इस पर्चे के परिणाम बताते हैं कि शाखा नेटवर्क के प्रत्याशित विस्तार से पिछड़े क्षेत्रों में ऋण मध्यस्थता में काफी सुधार हुआ है। यह, भारतीय रिज़र्व बैंक की 18 मई 2017 की मौजूदा शाखा प्राधिकरण नीति की भावना और सार की पुष्टि करता है, जिससे बैंकों को टीयर 5 और टीयर 6 यूआरसी में और अधिक शाखाएं खोलने के लिए प्रेरित किया जा सके।

प्रस्तावना के बाद, एडीपी की विशेषताएं खंड II में प्रस्तुत की गई हैं। खंड III साहित्य की समीक्षा प्रस्तुत करता है और खंड IV में डेटा स्रोत और वर्णनात्मक आँकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इसके बाद, खंड V में निरूपण क्रियाविधि दी गई है। खंड VI में प्रतिगमन

^ लेखक, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, कोलकाता से संबद्ध हैं। लेखकगण, श्री गुनवीर सिंह, मु.म.प्र., कोलकाता के प्रति उनकी टिप्पणियों के लिए आभारी हैं। आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों।

परिणाम प्रस्तुत किया गया है और खंड VII में निष्कर्ष दिया गया है।

II. आकांक्षी जिला कार्यक्रम

एडीपी के तहत पिछड़े जिलों[1] को विकसित करने के लिए केंद्रीय और राज्य योजनाओं का अभिसरण, विकास के हितधारकों के बीच सहयोग और जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा की परिकल्पना की गई है। एडीपी के तहत भागीदारी के लिए पात्र जिलों का चयन एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था। गरीबी, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा और अवसंरचना जैसे चार अलग-अलग हिस्सों के ग्यारह संकेतकों का उपयोग किया गया। चयन प्रक्रिया में उस संकेतक द्वारा व्यक्त पक्ष के सापेक्ष महत्व को दर्शाने के लिए प्रत्येक संकेतक को एक भार दिया गया था। उपयोग किए गए संकेतक, संकेतक के आयाम, डेटा स्रोत और संकेतकों से जुड़े भार सारणी 1 में दिए गए हैं। इसके अलावा, राज्यों ने किसी बदलाव का सुझाव देने के लिए जिलों की सूची की समीक्षा की।

सारणी 1 : आकांक्षी जिलों की चयन प्रक्रिया - संकेतक

संकेतक	क्षेत्र	स्रोत	भार
भूमिहीन परिवार शारीरिक श्रम पर निर्भर हैं	गरिबी	(सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना-गरिबी 7)	25%
प्रसवपूर्व देखभाल	स्वास्थ्य और पोषण	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-4)	7.5%
संस्थागत डिलिवरी		(एनएफएचएस-4)	7.5%
5 साल से कम उम्र के बच्चों का स्टंटिंग		(एनएफएचएस-4)	7.5%
5 साल से कम उम्र के बच्चों में वेस्टिंग		(एनएफएचएस-4)	7.5%
प्रारंभिक ड्रॉप-आउट दर (शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली) (यू-डीआईएसई)	शिक्षा	(यू-डाईस 2015-16)	7.5%
प्रतिकूल छात्र शिक्षक अनुपात		(यू-डाईस 2015-16)	7.5%
गैर-विद्युतीकृत घर	अवसंरचना	(ऊर्जा मंत्रालय)	7.5%
जिन घरों में व्यक्तिगत शौचालय नहीं है		(पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय)	7.5%
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) से असंबद्ध गांव		(ग्रामीण विकास मंत्रालय)	7.5%
ग्रामीण घरों में पानी की सुविधा नहीं है		(पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय)	7.5%
कुल			**100%**

स्रोत: वेबसाइट, एडीपी।

एडीपी की मुख्य रणनीति, राज्यों को जमीनी स्तर के विकास के मुख्य संचालकों के रूप में देखना है। यह कार्यक्रम प्रत्येक जिले की ताकत की पहचान करता है और विभिन्न हितधारकों की भागीदारी के माध्यम से और पहचान किए गए क्षेत्रों में विभिन्न राज्य और केंद्रीय योजनाओं को समेकित कर जिले के समग्र विकास के लिए उन शक्तियों को एक उत्प्रेरक के रूप में बदलने का प्रयास करता है। एडीपी के लिए आवश्यक है कि जिलों को राज्य का सर्वश्रेष्ठ और उसके बाद देश का सर्वश्रेष्ठ बनने की ख्वाहिश रखनी चाहिए। जिलों के बीच विकास में प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए एडीपी में इस तत्व की शुरुआत की गई है।

एडीपी में पांच विषय हैं: (1) स्वास्थ्य और पोषण, (2) शिक्षा, (3) कृषि और जल संसाधन, (4) वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, और (5) अवसंरचना। इस कार्यक्रम के तहत इन विषयों में से प्रत्येक को एक विशिष्ट भार दिया गया है जो मोटे तौर पर समग्र कार्यक्रम ढांचे में संबंधित विषयों के महत्व को दर्शाता है। उच्चतम भार (30 प्रतिशत) दो विषयों, स्वास्थ्य और पोषण, और शिक्षा को दिया गया है, इसके बाद कृषि और जल संसाधन (20 प्रतिशत) को रखा गया है। अवसंरचना को 10 प्रतिशत भार दिया गया है। वित्तीय समावेशन और कौशल विकास (सारणी 2) को सबसे कम भार (पांच प्रतिशत) दिया गया है। इन पांच विषयों में, कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से हुई प्रगति की बारीकी से निगरानी करने के लिए 81 डेटा बिंदुओं के आधार पर 49 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) की पहचान की गई है और इसे एक डैशबोर्ड के माध्यम से व्यक्त किया गया है।

सारणी 2: भार के साथ एडीपी की थीम

विषय	भार
स्वास्थ्य और पोषण	30
शिक्षा	30
कृषि और जल संसाधन	20
अवसंरचना	10
वित्तीय समावेशन	5
कौशल विकास	5
कुल	**100**

स्रोत: वेबसाइट, एडीपी।

[1] प्रारंभ में, कार्यक्रम के लिए 117 जिलों का चयन किया गया था, हालांकि, पश्चिम बंगाल ने कार्यक्रम में भाग नहीं लेने का फैसला किया, फिर भी केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल से पांच जिलों का चयन किया गया था।

वित्तीय समावेशन पर संकेतक जन धन योजना के तहत खाते खोलने, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जैसे केंद्र सरकार के कार्यक्रमों में भागीदारी और मुद्रा ऋणों के संवितरण में किए गए सुधार को ट्रैक करते हैं। विशेष रूप से, सी-डी अनुपात एडीपी की वित्तीय समावेशन थीम का केपीआई नहीं है। हालांकि, वित्तीय समावेशन विषय के तहत निगरानी रखने वाले कुछ केपीआई, जैसे- मुद्रा ऋणों का वितरण, इन जिलों में उच्च ऋण प्रवाह का परिणाम हो सकता है (सारणी 3)।

इसके अलावा, एडीपी के अन्य विषयों जैसे "कृषि ऋण में प्रतिशत वृद्धि" और बैंकिंग प्रणाली के साथ ऋण संपर्क के तहत निगरानी रखने वाले कुछ केपीआई भी आकांक्षी जिलों के सी-डी अनुपात को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं (सारणी 4)। इसके अलावा, एडीपी के समग्र रोल आउट से विभिन्न गतिविधियों के लिए बैंक वित्तपोषण को भी बढ़ावा मिल सकता है,

सारणी 3: वित्तीय समावेशन विषय - संकेतक

विषय	संकेतक
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना:	प्रति 1 लाख जनसंख्या पर मुद्रा ऋण का कुल संवितरण (रुपये में)। बैंकिंग सेवा केन्द्रों विशेषकर बैंकिंग संपर्की नेटवर्क की संख्या में वृद्धि करना। ऋण आवेदनों का समय पर निस्तारण जागरूकता पैदा करना और मुद्रा डेबिट कार्ड को अपनाने और उपयोग को प्रोत्साहित करना।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना:	प्रति 1 लाख जनसंख्या पर नामांकन की संख्या दावेदार/नामिती बैंक खाते में राशि का सीधा अंतरण सक्षम करना। योजना को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), मुद्रा ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और अन्य ऋणों के साथ जोड़ा जाना।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना: चरण:	प्रति 1 लाख जनसंख्या पर नामांकन की संख्या दावेदार/नामिती बैंक खाते में राशि का प्रत्यक्ष अंतरण सक्षम करें। डीबीटी, मुद्रा ऋण, केसीसी ऋण और अन्य ऋण के साथ जोड़ी गई योजना।
एनएपीएस (राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना),	पूरा करने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या / पोर्टल पर पंजीकृत प्रशिक्षुओं की कुल संख्या
एनएटीएस (राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना)	डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से स्टाइपेंड का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना।

स्रोत: वेबसाइट, एडीपी।

सारणी 4 : सी-डी अनुपात को सीधे प्रभावित करने वाले संकेतक

विषय	संकेतक
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	जिला सिंचाई योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। सूक्ष्म सिंचाई के लिए संभावित क्षेत्र की पहचान सुनिश्चित करना और लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप देना। बैंकों के साथ साख जुड़ाव को अंतिम रूप देना।
कृषि ऋण में प्रतिशत वृद्धि	अल्पावधि फसली ऋणों के लिए ब्याज अनुदान योजना। नाबार्ड की जिला क्रेडिट लिंक योजना लागू करना सुनिश्चित करना। जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित करना सुनिश्चित करना। पैक्स (प्राथमिक कृषि साख समिति) का बैंकों के साथ एकीकरण सुनिश्चित करना। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाना सुनिश्चित करना। तिमाही प्रगति की समीक्षा।

स्रोत: वेबसाइट, एडीपी।

जिससे विभिन्न क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित कर इन जिलों में अधिक ऋण आपूर्ति हो सकती है।

III. साहित्य की समीक्षा

1930 के दशक की शुरुआत में ,आर्थिक संवृद्धि और ऋण मध्यस्थीकरण के बीच संबंध को उजागर किया गया था, क्योंकि वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाएं, जुटाई गई बचत को, जरूरतमंद फर्मों के बीच वितरित करते हैं जिससे आर्थिक संवृद्धि गति प्राप्त करता है। इसके अलावा, कई आर्थिक संवृद्धि मॉडल, जैसे कि सोलो मॉडल, आर्थिक संवृद्धि के मुख्य चालक के रूप में पूंजी संचय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाएं, अधिशेष वाले आर्थिक एजेंटों से उधारकर्ताओं तक बचत की गति को बढ़ाते हैं और वे, सुरक्षा और ब्याज आय जैसे बचत के लाभों का प्रचार कर अर्थव्यवस्था में बचत दर को बढ़ाते हैं। कुछ अध्ययनों ने आर्थिक संवृद्धि को प्रेरित करने या आर्थिक संवृद्धि के किसी भी स्रोत, जैसे कि बचत दरों और पूंजी संचय (जयरत्ने और स्ट्रहान, 1996; डेमिरगुक-कुंट और मक्सिमोविच, 1998; राजन और ज़िंगलेस, 1998; बेक और अन्य, 2000; किंग और लेविन, 1993; लेविन, 1997; बेक और लेविन, 2004) को प्रेरित करने में वित्तीय

मध्यवर्ती संस्थाओं द्वारा निभाई गई भूमिका की पुष्टि की है। इसके अलावा, वित्तीय विकास और आर्थिक संवृद्धि के बीच एक दीर्घकालिक सह-सन्निवेशात्मक (को-इंटीग्रेटिंग) संबंध की भी पुष्टि की गई है (बिस्ट और रॉबर्ट, 2018)। हालांकि, इस बात के प्रमाण हैं कि एक न्यूनतम सीमा से अधिक वित्तीय विकास आर्थिक संवृद्धि को आगे नहीं बढ़ाता है। इस प्रकार, प्रत्येक देश के लिए, वित्तीय विकास का एक इष्टतम स्तर मौजूद होता है जो आर्थिक संवृद्धि को गति देता है (शेन और ली, 2006; लॉ और निर्विकार, 2014; अकैंड और अन्य, 2012; सेचेट्टी और खारौबी, 2012)।

पूर्वी क्षेत्र[2] देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत कम वित्तीय विकास रिपोर्ट करता है (आरबीआईए, विभिन्न वर्ष; आरबीआईबी, विभिन्न वर्ष; राजेश और अन्वेषा, 2019)। पूर्वी क्षेत्र के वित्तीय विकास या ऋण मध्यस्थीकरण की चुनौतियों को उजागर करने वाले अध्ययन या तो राज्य-स्तरीय विश्लेषण या प्राथमिक सर्वेक्षण-आधारित विश्लेषण तक ही सीमित हैं। ये पहले के अध्ययन कुछ व्यापक मुद्दों और चुनौतियों को सामने लाते हैं, जैसे कि आय बढ़ाने, औद्योगिक आधार और अवसंरचना विकसित करने के लिए नीतियां जो इस क्षेत्र में ऋण उठाव बढ़ाने पर ध्यान दे (राजेश और अन्वेषा, 2019)। चूँकि, पूर्वी क्षेत्र, जिसमें पूर्वी और उत्तर-पूर्वी दोनों क्षेत्र शामिल हैं, भारत में पिछड़े क्षेत्रों में से एक है, अध्ययनों के एक दूसरे सेट ने इस क्षेत्र के ऋण मध्यस्थीकरण या विकास में सूक्ष्म-वित्त की भूमिका की पड़ताल की है (कृष्णनकुट्टी, 2011; पाटीकर और हरिदेव, 2012; चानू और शिबू, 2014; नाथ और लिजुम, 2014; देब और सांता, 2016; दास और पटनायक, 2015; पाल और सिंह, 2019)। सामान्य तौर पर, इन अध्ययनों ने इस क्षेत्र में ऋण-उठाव में सुधार के लिए सूक्ष्म-वित्त के दायरे पर ध्यान दिया।

यह अध्ययन एक अलग प्रश्न की चर्चा करके मौजूदा साहित्य से विचलित हो जाता है; आकांक्षी जिले, पिछड़ेपन के करीब होने के बावजूद, सी-डी अनुपात के माध्यम से ऋण मध्यस्थता के भिन्न स्तरों को क्यों दर्शाते हैं? चूँकि, इन जिलों को सरकार द्वारा अपने एडीपी के तहत पिछड़े जिले के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यह अध्ययन, पूर्वी क्षेत्र में 56 आकांक्षी जिलों से संबंधित डेटा का उपयोग कर, इस प्रश्न का उत्तर देता है। इस पर्चे के नीतिगत सुझाव पूर्वी क्षेत्र में ऋण मध्यस्थता के समग्र सुधार में योगदान देंगे। भारत के आकांक्षी जिलों पर बढ़ते साहित्य को भी इस अध्ययन के निष्कर्षों से लाभ होगा।

IV. आंकड़े और वर्णनात्मक सांख्यिकी

अर्थमितीय मॉडल के लिए, 2010-11 से 2019-20 के बीच की अवधि डेटा को विचारार्थ लिया गया है। एडीपी को 2017-18 के दौरान लागू किया गया था। इसलिए, प्रतिगमन (रिग्रेशन) के लिए, पहले और बाद के एडीपी, डेटा को मोटे तौर पर दस वर्षों तक सीमित रखा गया है। सिस्टम जीएमएम ढांचे में होने वाले उपकरणों के प्रसार की समस्या को रोकने के लिए डेटा अवधि 10 साल तक सीमित कर दी गई है क्योंकि इस ढांचे में समय अवधि की संख्या में उपकरणों की संख्या द्विघातिक है। ऋण मध्यस्थता पर कोविड-19 महामारी के कारण होने वाले विपथन से बचने के लिए 2019-20 तक के डेटा लिए गए हैं। जिला स्तर पर ऋण, जमाराशि और शाखाओं से संबंधित आँकड़े आरबीआई की मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियों (बीएसआर) से प्राप्त किए गए हैं। इन आंकड़ों में केवल वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं। विभिन्न राज्यों की राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) से वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों सहित जिला स्तरीय ऋण और जमाराशि डेटा उपलब्ध हैं। हालांकि, राज्य एसएलबीसी संपूर्ण अध्ययन अवधि के लिए डेटा प्रदान नहीं कर सके और इस प्रकार संपूर्ण डेटासेट बीएसआर से प्राप्त किया गया है और वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित है। जिलों के क्षेत्र अध्ययन के तहत जिलों की संबंधित वेबसाइटों से लिए गए हैं। अध्ययन में शामिल करने के लिए जिले के घरेलू उत्पादों के आंकड़े सतत उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए, खेती के प्रमुख फसल की उपज का डेटा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित फसल उत्पादन सांख्यिकी से लेकर जिला स्तर पर प्रॉक्सी ऋण मांग तक से लिया गया है।

पूर्वी क्षेत्र के आकांक्षी जिलों में सी-डी अनुपात 40 प्रतिशत के माध्य के मुताबिक विभाजित किया जाता है और यह काफी विषम है, जैसा कि उच्च मानक विचलन (सारणी 5) के माध्यम से परिलक्षित होता है। इसके अलावा, 35 प्रतिशत माध्यिका सुझाव

[2] इस अध्ययन में, पूर्वी क्षेत्र में,पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा , असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं।

सारणी 5: जिला प्रोफाइल

मानक (इकाई)	माध्य	माध्यिका	मानक विचलन	न्यूनतम	अधिकतम
सी-डी अनुपात (प्रतिशत)	39.6	34.9	17.1	10.7	96.3
प्रति खाता क्रेडिट (₹/हज़ार)	129.1	102.8	61.9	65.9	337.7
प्रति खाता जमा (₹/हजार)	28.9	23.1	21.1	11.3	132.5
क्षेत्र प्रति शाखा (वर्ग किमी)	58.9	32.4	83.8	8.4	525.0
बैंक शाखाओं की संख्या	112.7	100.0	90.2	4.0	472.0
कृषि ऋण खातों का हिस्सा (प्रतिशत)	57.1	59.8	14.8	5.1	77.7
कृषि में मुख्य श्रमिकों का हिस्सा (प्रतिशत)	65.2	66.5	13.8	17.8	84.5
प्रमुख फसल की उपज (टन/हेक्टेयर)	2.6	2.5	0.9	0.9	7.1
प्रमुख फसल का क्षेत्र हिस्सा (अनुपात)	0.2	0.2	0.1	0.0	0.5

नोट: कोविड-19 के कारण विचलन से बचने के लिए, वर्णनात्मक आंकड़े एक पूर्व-महामारी वर्ष यानी 2019-20 के आंकड़ों पर आधारित हैं।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ प्राक्कलन।

देती है कि केवल कुछ जिले माध्य के दाईं ओर स्थित हैं जिनका सी-डी अनुपात बहुत अधिक हो सकता है, जबकि एक समूह अपने सी-डी अनुपात के औसत के बाईं ओर होने के साथ निम्न प्रदर्शन करने वाला बना रहता है। प्रति खाता ऋण के साथ-साथ प्रति खाता जमाराशि के लिए एक समान प्रवृत्ति देखी जा सकती है, जिसमें पूर्व में बहुत उच्च मानक विचलन है। यह ऋण लेने के मामले में जिलों के बीच उच्च विषमता का संकेत देता है। प्रति शाखा क्षेत्र और बैंक शाखा के आँकड़ों को देखते हुए, पूर्वी क्षेत्र के आकांक्षी जिलों में बैंकिंग सेवाओं के प्रवेश में उच्च भिन्नता का संकेत देते हुए, जिलों के बीच भिन्नता और भी अधिक दिखाई देती है।

कृषि इन जिलों की आर्थिक गतिविधियों पर हावी है, यह कृषि क्षेत्र में 60 प्रतिशत से अधिक मुख्य श्रमिकों की औसत हिस्सेदारी से परिलक्षित होता है। इसके अलावा, कृषि के लिए ऋण खातों में 50 प्रतिशत से अधिक की औसत हिस्सेदारी, उनकी आजीविका के लिए इस क्षेत्र पर परिवारों की एक मजबूत निर्भरता दर्शाती है। इन जिलों में कृषि गतिविधि की गहनता में अंतर कम रहता है, जैसा कि प्रत्येक जिले की प्रमुख फसल की उपज और क्षेत्र-हिस्सेदारी दोनों में नगण्य मानक विचलन के पता चलता है, इस प्रकार पूर्वी क्षेत्र के आकांक्षी जिलों में समान ऋण-मांग की संभावना दिखती है।

कई आकांक्षी जिले (मार्च 2020 के आंकड़ों के अनुसार 39) पूर्वी क्षेत्र के औसत सी-डी अनुपात 43.4 प्रतिशत[3] (चार्ट 1) की

चार्ट 1 : सी-डी अनुपात पूर्वी क्षेत्र आकांक्षी जिला

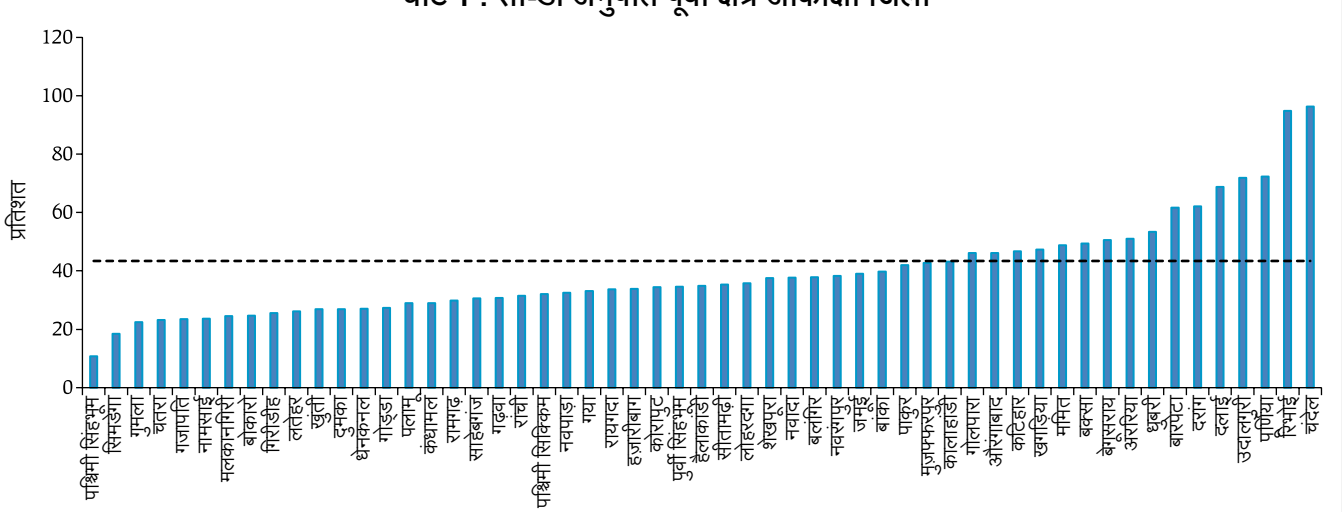

स्रोत: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशि और ऋण से संबंधित तिमाही आँकड़े, आरबीआई।

[3] मार्च 2020 अंत को कोविड-19 के कारण विपथन से बचने के लिए चुना गया है

सारणी 6 : पूर्वी क्षेत्र औसत सी-डी अनुपात की तुलना में कम सी-डी अनुपात वाले आकांक्षी जिलों का राज्यवार वितरण

राज्य	जिला
झारखंड	(#19) प. सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, चतरा, बोकारो, दुमका, गोड्डा, लातेहर, साहिबगंज, रामगढ़, खूंटी, गिरिडीह, रांची, गढ़वा, हजारीबाग, पू. सिंहभूम, लोहरदगा, पलामू, पाकुड़
उड़ीसा	(#10) गजपति, मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, नवापारा, बलांगीर, धेनकनल, कंधमल, कालाहांडी, नौपाड़ा
बिहार	(#7) शेखपुरा, गया, नवादा, जमुई, बांका, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर
असम	(#1) हैलाकांडी
अरुणाचल प्रदेश	(#1) नमसाई
सिक्किम	(#1) पश्चिम सिक्किम

नोट: 1. पश्चिम बंगाल, आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम में आधिकारिक रूप से भाग नहीं ले रहा है, हालांकि पश्चिम बंगाल के पांच जिलों, अर्थात्, दक्षिण दिनाजपुर, मालदह, मुर्शिदाबाद, बीरभूम और नदिया को शुरू में केंद्र सरकार द्वारा कार्यक्रम के तहत भागीदारी के लिए पात्र के रूप में पहचाना गया था।

2. पूर्वी क्षेत्र औसत सी-डी अनुपात की तुलना में कम सी-डी अनुपात वाले पूर्वी क्षेत्र के आकांक्षी जिले इस सारणी में रिपोर्ट किए गए छह राज्यों से संबंधित हैं। चार उत्तर-पूर्व क्षेत्र (एनईआर) राज्यों के लिए आकांक्षी जिले - मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय ने मार्च 2020 तक पूर्वी क्षेत्र औसत से अधिक सी-डी अनुपात दर्ज किया है। नागालैंड में एकमात्र आकांक्षी जिले किफिर के लिए, डेटा केवल 2016-17 तक उपलब्ध है।

तुलना में कम सीडी अनुपात की रिपोर्ट करते हैं। ये जिले छह पूर्वी क्षेत्र के राज्यों से संबंधित हैं, अर्थात झारखंड, बिहार, उड़ीसा , असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। आकांक्षी जिलों के राज्य-वार वितरण से पता चलता है कि पूर्वी क्षेत्र के औसत से कम सीडी अनुपात की रिपोर्ट करने वाले अधिकांश जिले झारखंड के हैं और उसके बाद उड़ीसा (सारणी 6) का स्थान है।

IV. निरूपण क्रियाविधि

सिस्टम जीएमएम, इस विषय की जांच करने के लिए एक उपयुक्त ढांचा है क्योंकि यह गतिज पैनल ढांचे में, सी-डी अनुपात के साथ बैंकिंग सेवाओं की आपूर्ति और बैंकिंग सेवाओं की मांग के बीच अंतर्जातता को प्रभावी रूप से नियंत्रित करता है। सिस्टम जीएमएम प्राक्कलन में इस संबंध को मॉडल करने के लिए स्तरों के साथ-साथ अंतरों में समीकरण शामिल हैं। यह एक स्टैक्ड डेटासेट का उपयोग करता है जिसमें डेटासेट में प्रत्येक जिले के लिए रूपांतरित प्रेक्षण (अर्थात, भिन्न्ताओं में चर) के साथ-साथ अपरिवर्तित प्रेक्षण (स्तरों में चर) शामिल हैं। सिस्टम जीएमएम में, स्तर समीकरणों को विभेदित चरों का उपयोग कर और अंतर समीकरणों को स्तर चरों का उपयोग कर यंत्रित (इंटूमेंटेड) किया जाता है। गणितीय रूप में, अंतर समीकरण, फॉर्म समीकरण (1) लेगा, जहां $\Delta Yit-1$ को $Yit-2$ का उपयोग करके यंत्रित किया जाता है जैसा कि समीकरण (2) में दिखाया गया है। सिस्टम जीएमएम में स्तर समीकरण फॉर्म समीकरण (3) लेगा, जहां $Yit-1$ को $\Delta Yit-2$ का उपयोग करके इंस्ट्रूमेंट किया गया है जैसा कि समीकरण (4) में दिखाया गया है।

$$\Delta Yit = \alpha\Delta Yit-1 + \beta\Delta Xit + \Delta\varepsilon it \quad ...(1)$$

$$\Delta Yit = \alpha Yit-2 + \beta\Delta Xit + \Delta\varepsilon it \quad ...(2)$$

$$Yit = \alpha Yit-1 + \beta Xit + ui + \varepsilon it \quad ...(3)$$

$$Yit = \alpha\Delta Yit-2 + \beta Xit + ui + \varepsilon it \quad ...(4)$$

सिस्टम जीएमएम संपूर्ण समीकरणों को एक संबंध के रूप में मानती है क्योंकि अनिवार्य रूप से आश्रित और स्वतंत्र चर समान होते हैं। इसलिए, पैरामीटर α और β का प्राक्कलन दोनों स्तरों के साथ-साथ अंतर समीकरणों में निहित जानकारी का उपयोग करके लगाया जाता है। समीकरण (4) में व्यक्तिगत प्रभाव ui की उपस्थिति के कारण उत्पन्न अंतर्जातता की समस्या को एक आवश्यक स्थिति $\alpha < 1$ के साथ पूरे पैनल में व्यक्तिगत प्रभाव ui के विरुद्ध ऑटोरेग्रेसिव क्षय α के रद्द प्रभाव के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, जो प्रकृति डेटा जनरेट करने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। संक्षेप में, व्याख्या के लिए सिस्टम जीएमएम प्राक्कलन की वैधता हेतु सिस्टम को स्थिर और अभिसरणात्मक होना चाहिए (रूडमैन, 2009ए)।

अर्थमितीय मॉडल में, आश्रित चर, जिलों का सी-डी अनुपात है। स्वतंत्र चर प्रत्येक जिले में प्रति बैंक शाखा क्षेत्र और खेती के तहत जिले की प्रमुख फसल की उपज हैं। जहाँ, प्रति बैंक शाखा क्षेत्र, बैंकिंग सेवाओं की आपूर्ति के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य करता है, वहीं प्रमुख फसल की उपज को, बैंकिंग सेवाओं की मांग के लिए प्रॉक्सी के रूप में लिया जाता है। अधिकांश परिवार के अपनी आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर होने के कारण, प्रमुख फसल की उपज एक तरह से इन जिलों में आर्थिक गतिविधियों की सीमा और इसलिए ऋण की मांग को मापने के लिए एक अच्छे संकेतक के रूप में कार्य करती है।

V. प्रतिगमन परिणाम

प्रतिगमन परिणाम सारणी 7 में प्रदान किए गए हैं। सिस्टम जीएमएम प्राक्कलन में α की विश्वसनीय सीमा पर पहुंचने के लिए साधारण न्यूनतम वर्ग (ओएलएस) और न्यूनतम वर्ग डमी चर (एलएसडीवी) प्राक्कलन प्रयोग किए जाते हैं। जहाँ, ओएलएस लैग्ड डिपेंडेंट वेरिएबल और एरर टर्म के बीच धनात्मक सहसंबंध के कारण गुणांक को ऊपर की ओर बायस करता है, एलएसडीवी लैग्ड डिपेंडेंट वेरिएबल और एरर टर्म (रूडमैन, 2009बी) के बीच ऋणात्मक सहसंबंध के कारण गुणांक को नीचे की ओर बायस करता है। इस प्रकार, ओएलएस और एलएसडीवी अनुमानों द्वारा प्रदान की गई सीमा α के लिए एक विश्वसनीय सीमा के रूप में काम करती है जिसका उपयोग मॉडल के सही विनिर्देश को सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है। वर्तमान अध्ययन में अनुमानित α की विश्वसनीय सीमा 0.322 (α का एलएसडीवी प्राक्कलन) से 0.601 (α का ओएलएस प्राक्कलन) (बॉन्ड, 2002) है। चूँकि इस विश्वसनीय सीमा का ऊपरी मान एक से कम है, यह अभिसरण की उपस्थिति की ओर इशारा कर रहा है और इस प्रकार, स्थिर गतिज प्रणाली, जो सिस्टम जीएमएम के वैध होने के लिए एक आवश्यक शर्त है। चरों को उनके अंतर रूप में परिवर्तित करते समय, एक ओर्थोगोनल परिवर्तन का पालन किया जाता है क्योंकि यह केवल एक प्रेक्षण को घटाने के बजाय भविष्य में उपलब्ध सभी प्रेक्षणों के औसत को घटाता है। यह सैद्धांतिक रूप से मजबूत है, खासकर जब डेटा में कुछ प्रेक्षण लुप्त हैं।

सारणी 7 के कॉलम 4 में दिए गए सिस्टम जीएमएम के परिणाम उपकरणों की समाप्ति के बाद प्राक्कलन प्रदान करते हैं, जो पैनल डेटा में समूहों की संख्या की तुलना में उपकरणों की संख्या को व्याख्या के लिए वैध बनाता है। इस मॉडल में, 0.432 पर α का अनुमानित मूल्य ओएलएस और एलएसडीवी अनुमानों द्वारा अनुमानित विश्वसनीय सीमा के भीतर आता है। स्वसहसंबंध परीक्षण के साथ-साथ अति-पहचान परीक्षण आश्रित चरों में भिन्नताओं को समझाने में मॉडल की विश्वसनीयता का संकेत देते हुए अच्छा कार्य करते हैं।

कुल मिलाकर, यह मॉडल जमाराशि की तुलना में ऋण अनुपात को बढाने में बैंकिंग सेवाओं की आपूर्ति द्वारा निभाई गई

सारणी 7: प्रतिगमन परिणाम

चर	एलएसडीवी	ओएलएस	प्रणाली जीएमएम
1	2	3	4
आश्रित चर : जमारशि की तुलना में ऋण अनुपात			
एल1	0.322 (4.47)	0.601 (7.58)	0.432 (4.91)
एल2	0.125 (3.31)	0.337(5.11)	0.184(3.71)
एलएन (प्रति शाखा क्षेत्र)	-20.983 (-5.51)	0.669(1.29)	-25.524 (-2.96)
यील्ड1	-0.365 (-0.9)	0.994(2.12)	0.206 (0.38)
साल डमीज	परिणाम रिपोर्ट नहीं		
निश्चित प्रभाव	रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई।	-	-
एफ	109	94.64	-
प्रोब	0.000	0.000	-
आर स्क्वेयर्ड	0.8721	0.7661	-
रूट एमएसई	5.1574	6.6098	-
टिप्पणियों की संख्या	525	525	471
समूहों की संख्या	-	-	54
उपकरणों की संख्या	-	-	45
एआर के लिए अरेलानो-बॉन्ड टेस्ट (1)			-1.48 (0.14)
एआर के लिए अरेलानो-बॉन्ड टेस्ट (2)			-0.05 (0.95)
सरगन ओवरिड के लिए परीक्षण			53.03 (0.01)
ओवरिड के लिए हैनसेन परीक्षण			38.63 (0.19)
हैनसेन परीक्षण समूह को छोड़कर			30.20 (0.14)
अंतर (शून्य एच = बहिर्जात)			8.43 (0.49)

नोट: गुणांकों के साथ कोष्ठक में दिए गए आंकड़े टी-अनुपात हैं।
उपज 1: जिले की पहली प्रमुख फसल की उपज
एल1: सी-डी अनुपात का लैग एक
एल2: सी-डी अनुपात का लैग टू

प्रमुख भूमिका का प्रमाण देता है। बैंकिंग सेवाओं की आपूर्ति पर गुणांक ऋणात्मक और महत्वपूर्ण है जो दर्शाता है कि जैसे-जैसे एक शाखा द्वारा सेवा क्षेत्र बढ़ता है, सी-डी अनुपात घटता जाता है। संबंधित जिलों में प्रमुख फसल की उपज के माध्यम से कैप्चर की गई बैंकिंग सेवाओं की मांग नगण्य हो जाती है। इस प्रकार, परिणाम दर्शाते हैं कि पिछड़े क्षेत्रों या अब तक बैंक रहित और कम बैंक वाले क्षेत्रों में, नई शाखाएं खोलने से बैंकिंग सेवाओं की मांग में वृद्धि होती है। हालांकि, जिला घरेलू उत्पादों और वाहन पंजीकरण जैसे क्रेडिट मांग के अन्य संभावित प्रॉक्सी पर समय शृंखला और जिलेवार डेटा की अनुपलब्धता, आगे की मजबूती की जांच करने की हमारी क्षमता को सीमित करती है।

VI. समापन टिप्पणी

आर्थिक गतिविधियों के वित्तपोषण द्वारा ऋण मध्यस्थीकरण, क्षेत्र के आर्थिक विकास में योगदान करती है। फिर भी, पिछड़े क्षेत्रों

में ऋण मध्यस्थीकरण में सुधार की गति धीमी है। भारत सरकार ने 2018 में सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के संकेतकों के आधार पर 117 जिलों को आकांक्षी के रूप में चुना। पूर्वी क्षेत्र में 56 आकांक्षी जिले हैं। ऋण मध्यस्थता का स्तर, जैसा कि सी-डी अनुपात के माध्यम से मापा जाता है, इन जिलों में भिन्न है। यह, इन पिछड़े जिलों में क्रेडिट मध्यस्थीकरण में भिन्नता के कारणों की जांच करने के लिए प्रेरित करता है।

बैंकिंग सेवाओं की आपूर्ति और सी-डी अनुपात के साथ बैंकिंग सेवाओं की मांग के बीच अंत: संबंध को नियंत्रित करने के बाद इस मुद्दे का एक गतिज पैनल ढांचे में विश्लेषण किया गया था। एक जिले में एक बैंक शाखा द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले औसत क्षेत्र का उपयोग करके बैंकिंग सेवाओं की आपूर्ति प्राक्कलित की जाती है। जिलों की प्रमुख फसल की उपज के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं की मांग को कैप्चर किया गया है।

प्रतिगमन परिणाम दिखाते हैं कि बैंकिंग सेवाओं की आपूर्ति मुख्य कारक है जो पूर्वी क्षेत्र के आकांक्षी जिलों में सी-डी अनुपात को संचालित करता है। परिणाम, बैंक शाखा नेटवर्क को देश के आंतरिक क्षेत्रों में फैलाने के महत्व को रेखांकित करते हैं। बैंक शाखा नेटवर्क के संभावित प्रसार में, औपचारिक बैंकिंग चैनलों में क्रेडिट के साथ-साथ, बचत के लिए अभी तक पूरी न की गई मांग को पूरा करने की क्षमता है - इस प्रकार, सी-डी अनुपात को बढ़ावा मिलता है। बैंक पूंजी द्वारा आर्थिक गतिविधियों का वित्तपोषण, आर्थिक विकास पर सकारात्मक बाह्यताओं के माध्यम से ऋण की मांग को और बढ़ा सकता है। इस प्रकार, पिछड़े क्षेत्रों में कम बैंकिंग कारोबार के कारण कथित कम शाखा व्यवहार्यता से इन जिलों में शाखा विस्तार प्रक्रिया को धीमी नहीं होनी चाहिए।

संदर्भ:

Arcand, J.L., Berkes, E., Panizza, U., (2012), 'Too Much Finance?', IMF Working Paper, 12/ 161.

Arellano, M., and O. Bover, (1995), 'Another look at the instrumental variable estimation of error-components models', Journal of Econometrics, 68: 29–51.

Arellano, M., and S. Bond. (1991), 'Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations', Review of Economic Studies, 58: 277–297.

Beck T and Levine R., (2004), 'Stock Markets, Banks and Growth: Panel Evidence', Journal of Banking and Finance, 28(3): 423-442.

Beck T, Levine R., Loayza N (2000), 'Finance and sources of growth', Journal of financial economics, 58(1- 2): 261-300.

Bist, Jagadish Prasad and Robert Read (Reviewing Editor), (2018), "Financial development and economic growth: Evidence from a panel of 16 African and non-African low-income countries", Cogent Economics & Finance, 6:1.

Blundell, R., and S. Bond. (1998), 'Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models', Journal of Econometrics, 87: 115–143.

Bond, S. (2002), 'Dynamic panel data models: A guide to micro data methods and practice', Working Paper CWP09/02, Cemmap, Institute for Fiscal Studies, Available at http://cemmap.ifs.org.uk/wps/cwp0209.pdf.

Cecchetti, G., Kharroubi, E., (2012), 'Reassessing the Impact of Finance on Growth', BIS Working Papers No. 381, Bank for International Settlements.

Chanu and Shibu, (2014), 'MFIs of North East India: An Efficiency Analysis', International Journal of Banking, Risk and Insurance, 2(2), pp: 46-53.

Das and Patnaik, (2015), 'Micro Finance in Eastern India: The Role Played by Regional Rural Banks', Indian Journal of Finance, 9(11), pp: 45-59, November.

Deb and Santa, (2016), 'Financial Performance of Micro Finance Institutions in North East India. Pranjana: The Journal of Management Awareness', 19(2), p47-57.

Deb, Joyeeta; Kar, Santa, (2016), 'Financial Performance of Micro Finance Institutions in North East India', Pranjana: The Journal of Management Awareness, Vol. 19, Issue 2, p: 47-57.

DemirguKc7-Kunt, A., Maksimovic, V., (1998), 'Law, "finance, and "firm growth', Journal of Finance, 53: 2107-2137.

Government of India, (2021), 'Crop Production Statistics for Selected States, Crops and Range of Year', Available at https://aps.dac.gov.in/APY/Public_Report1.aspx

Government of India, (2021), 'National Family Health Survey – District Fact Sheets'. Available at http://rchiips.org/nfhs/

Jayaratne, J., Strahan, P., (1996), 'The "finance-growth nexus: evidence from bank branch deregulation', Quarterly Journal of Economics, 111: 639-670.

King G.R. and Levine R, (1993), 'Finance and Growth: Schumpeter might be Right', Quarterly Journal of Economics, 108 (3): 717-737.

Krishnankutty, (2011), 'Role of Banks Credit in Economic Growth: A Study with Special Reference to North East India', The Economic Research Guardian, 1(2).

Law, Siong Hook and Nirvikar Singh (2014), 'Does too much Finance Harm Economic Growth?', Journal of Banking and Finance, 41: 36-44.

Levine R. (1997), 'Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda', Journal of Economic Literature, 35 (2): 688-726.

Nath and Lijum, (2014), 'Micro Finance in the North Eastern Region of India: Opportunities and Challenges (Special Focus on Arunachal Pradesh)', Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 4(12), PP – 104-111.

NITI Aayog, (2018), 'Deep Dive: Insights from Champions of Change. The Aspirational Districts Dashboard', Available at https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2018-12/FirstDeltaRanking-May2018-AspirationalRanking.pdf

NITI Aayog. (2018), 'Transformation of Aspirational Districts', Available at https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2018-12/AspirationalDistrictsBaselineRankingMarch2018.pdf

Official Websites of aspirational districts.

Pal and Singh, (2019), 'Do Socially Motivated Self-Help Groups Perform Better? Exploring determinants of micro-credit groups' performance in Eastern India', Annals of Public and Cooperative Economics, 92(4).

Patikar and Haridev, (2012), 'Need and Progress of Micro-Finance in North-East India: An Evaluation', IASSI Quarterly, 31(2), Pp: 24-37.

Rajan R. and Zingales L., (1998), 'Financial Dependence and Growth', American Economic Review, 88(3): 559-586.

Rajesh, Raj and Anwesha Das. (2019), 'Drivers of Credit Penetration in Eastern India', RBI Monthly Bulletin, October.

RBIa. (Various years), Basic Statistical Returns.

RBIb. (Various years), Report on Trend and Progress of Banking in India.

Roodman, D. M. (2009a), 'A note on the theme of too many instruments', Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 71: 135–158.

Roodman, D. M. (2009b), 'How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata', Stata Journal, 9(1):86-136.

Shen C.H. and Lee CC, (2006), 'Same Financial Development but Different Economic Growth – Why?', Journal of Money, Credit and Banking, 38(7): 1907-1944.